3281

ग्रामीण राजनीतिक परिवर्तन में आरक्षण की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन
(मुजफ्फरनगर जिले के विशेष सन्दर्भ में)

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से
राजनीति विज्ञान विषय में पीएच०डी० उपाधि हेतु
प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध का सारांश

(24)

शोध निर्देशक
डॉ० दानवीर सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर
एस०डी० (पी०जी०) कॉलेज,
मुजफ्फरनगर

शोधार्थी
सुमित कुमार

शोध केन्द्र
राजनीति विज्ञान विभाग
एस०डी० (पी०जी०) कॉलेज, मुजफ्फरनगर

सारांश (ABSTRACT)

प्रस्तुत शोध प्रबंध के अन्तर्गत भारत की राजनीतिक व्यवस्था में जन सामान्य की भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के स्वरूप को विश्लेषणात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। जिसमें मूल रूप से लोककल्याण राज्य एवं संवैधानिक रूप से प्रस्तावित संवैधानिक आरक्षण (सकारात्मक कार्यवाही) की प्रक्रिया को माध्यम निश्चित किया गया है। वैश्विक स्तर पर बदलते राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आयामों ने बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक न्याय एवं सामाजिक कल्याण की सैद्धान्तिक व्यवहारिक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत किया। जिसने राष्ट्र–राज्य के निर्माण की समस्त प्रक्रियाओं में जन सामान्य की भागीदारी एवं अधिकारों को प्राथमिकता दी गई। भारत में आरक्षण के निर्धारण का मूल उद्देश्य विविधता एवं असमानता से व्याप्त समाज में राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक बराबरी के स्तर पर संसाधनों के वितरण को प्रोत्साहन देना है, अर्थात् "आरक्षण का उद्देश्य सुविधाहीन, शोषित एवं वंचित वर्गों को विशेष रूप में रियासतें देने के अधिकारों को दान व परोपकार के उद्देश्य के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता। इन अधिकारों को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15, 16, 29, 38, 46, 330, 332, 334, 335 आदि में व्याख्यात्मक एवं सशर्त रूप से प्रस्तुत किया गया है। जिनके अन्तर्गत शैक्षिक सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक आधारों पर विशेष वरीयता दी गई है जिसमें ऐतिहासिक रूप से पिछड़ी जाति एवं जनजातियों को विशेष संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत वरीयता देकर राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक संसाधनों पर अधिकार की विशेष प्राप्ति की गई है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध में राजनीतिक सहभागिता को केन्दित करते हुए ग्रामीण अंचलों में राजनीतिक परिवर्तन एवं जागरूकता को विशेष महत्व की उद्देश्य के साथ आरक्षण की भूमिका को सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक स्तर पर परीक्षण विश्लेषण स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध में प्रथम अध्याय में समस्या के अनुरूप राजनीतिक पृष्ठभूमि में आरक्षण की भूमिका का अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय अध्याय में आरक्षण के सैद्धान्तिक एवं संवैधानिक प्रावधानों को विश्लेषणात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। तृतीय अध्याय में शोध समस्या के अनुरूप ग्रामीण अंचलों में आरक्षण की भूमिका का सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। चतुर्थ अध्याय में शोध साहित्य का अवलोकन किया गया है। पंचम अध्याय में शोध समस्या में चयनित क्षेत्र का वर्णन एवं छठे अध्याय शोध क्षेत्र में सुनिश्चित की गई प्रश्नावली के अनुसार प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह एवं सारणी करण कर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है एव अंतिम अध्याय में शोध की परिकल्पनाओं का परीक्षण एवं समस्या समाधान के साथ सुझावों को प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में शोध को अन्तिम देने रूप एवं सिद्धान्त एक व्यावहारिक पक्ष को स्पष्ट करने के लिए चयनित किए गए अध्ययन क्षेत्र के तीन विकास खण्डों से 5–5 गाँव का चयन किया गया, जिसमें तैयार की गई अनुसूची के अनुसार संबंधित क्षेत्र के आम नागरिक राजनीतिक प्रतिनिधि एवं प्रशासनिक क्षेत्र से प्राथमिक आंकड़ों का संकलन किया गया जिसके आधार पर आरक्षण के बुनियादी स्वरूप को पहचाना गया।

निष्कर्ष रूप में, शोध में भारतीय ग्रामीण समाज में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन में आरक्षण की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है। जिससे समाज में वंशानुगत, पुरूष प्रधान, जातिवाद एवं लिंग आधारित भेदभाव पर नियंत्रण एवं ग्रामीण स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक ढांचे में बदलाव सुनिश्चित हुआ है। अतः आरक्षण भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली की विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त पर राजनीतिक स्वरूप में ग्रामीण जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने में सफल रही है। जिसके परिणामस्वरूप पिछड़े एवं संवेदनशील समुदाय का भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण के माध्यम से भारत की मुख्यधारा की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित हुई है।